लिए तथा दोनों देशों के बीच व्यापार संपर्क बढ़ाने के लिए जनवरी, 1988 से प्रयास किए गए है। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के तौर-तरीके निश्चित करने के लिए मंत्रीस्तरीय तथा पाकिस्तान में उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श किया गया है।

Drought Assistance to Rajasthan

@771. SHRi SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the details of the amount given as grant and adjusted against the plan allocation for the State of Rajasthan as drought assistance for the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE *m* THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Grant component of Advance Plan assistance given to Rajasthan Government for drought relief and its adjustment against Central Assistance allocated for the State's Annual Plan for 1988-89 is as follows: —

(Rs, in i crores)

Year	Grant *t* cTU/nnent of Mvance Plan assistance	\.djustment in 1988-89
1983-84 .	.	f 00-
1984-85 .		"'
1985-86 .	*t* 45	
1986-87 .	7 90	4 07
1987-88 .	9 09	

Note; 1. The grant portion forms 30 per cent of the total Advance Plan assistance and the balance 70 per cent is provided in the form of loans.

Note: 2. Advance Plan assistance for drought relief does not exceed 5 per cent of the Annual Plan outlay of the State for the corresponding year.

©Previously Unstarred **Question** No. 267, transferred from **the 4th** November, **1988.**

Central assistance in excess of 5 per cent in give in the form of 50 per cent grant and 50 per cent loan, not adjustable against Plan assistance. Note: 3. In addition to the above grants, non-adjustable grants have also been given for drought relief. They were as follows:—

Year	Amount (Rs. tti crores)
1983-84	3-24
1984-8S	
1985-86	25 95
1986-87	55 88
1987-88	190.02

संसाधित खाद्य का निर्यात

@@772. श्री राम जेठमलानी :
श्री राम नरेश यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 में छोटे और मझौले उद्योगों द्वारा किये गये संसाधित खाद्य वस्तुओं के कुल निर्यात उन वस्तुओं के कुल निर्यात के लगभग आधा था ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हाल में उद्योग के इस नये क्षेत्र में बड़े औद्योगिक घरानों के प्रवेश से छोटे और मझौले उद्योगों को बचाने और इस प्रवेश के फलस्वरूप उन पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० दास मुंशी) : (क) से (ग) लघु क्षेत्र संसाधित खाद्य मदों के कुल निर्यात का पर्याप्त भागीदार है। पापड़, अचार आदि

@@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 372,4 नवम्बर 1988 से स्थानान्तरित।

जैसी कुछ मदों में लघु क्षेत्र का योगदान विशेष रूप से बड़ा है। अनेक संसाधित खाद्य मदें श्रमिक प्रधान हैं जिनमें संयंत्र और मशीनों में कम निवेश होता है तथा ये लघु क्षेत्र में प्रचालन के लिए उपयुक्त हैं।

खाद्य संसाधन के क्षेत्र में बड़े सदनों को प्रवेश की अनुमति देते समय लघु क्षेत्र, कुटीर तथा खादी व ग्रामोद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य से खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

देश से निर्यातित मानव जातीय खाद्यों के मामले में लघु क्षेत्र तथा कुटीर उद्योग निरन्तर अग्रणीय भूमिका अदा करते रहेंगे।

लघु क्षेत्र अन्तिम निर्यात के लिए, पि सम्बन्धित कच्चे माल के मध्यवर्ती ससाधन में भी निरन्तर भूमिका अदा करता रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें लघु क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी है, खाद्य संसाधन क्षेत्र में बड़े सदनों के प्रवेश से उनपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Construction of Electric Crematoria

773. SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state;

(a) the number of electric crema toria proposed to be constructed, State-wise;

(b) whether these crematoria are likely to be completed during 1988-89; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) A total of 34 electric crematoria are being constructed under the Ganga Action Plan. Of , these, 4 will be in U.P., 9 in Bihar and 21 in West Bengal.

(b) and (c) During 1988-89, a total of 9 electric crematoria will be completed; 3 in U.P., 5 in Bihar and 1 in West Bengal.

Export of marine products

774. SHRI JAGADISH JANI; WU1 the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what steps Government have taken to step up export of marine products;

(b) the total amount of foreign exchange earned by Government out of export of marine products during the last three years; and

(c) what is the prospect of export of marine products during 1988-89?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) Goverment have taken various steps to step up export of marine products, which include promotion of prawn farming for augmenting production of cultured shrimps, encouragement of production of value added items like IQF (Individually Quick Frozen) shrimps, setting up of prawn hatcheries and measures for exploitation of deep sea fishery resources.

(b) The total amount of foreign exchange earned out of export of marine products during the last three years was:

1985-86	—	Rs. 398.00 crores
1986-87	—	Rs. 460.67 crores
1987-88	—	Rs. 531.20 crores

(c) Export of marine products durirng 1988-89 is likely to improve further.